IASBABA

One Stop Destination for UPSC/IAS Preparation

60 Days Week-7 & 8 Compilation

DELHI

5B, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi -110005. Landmark: Just 50m from Karol Bagh Metro Station, GATE No. 8 (Next to Croma Store)

Ph:0114167500

BANGALORE

#1737/37, MRCR Layout, Vijaynagar Service Road, Vijaynagar, Bangalore 560040. PH: 09035077800 / 7353277800

Q.1) सरकार की संघीय प्रणाली के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसमें दोहरी सरकार शामिल होती है।
2. संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी।
3. न्यायिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.1) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य

संघीय सरकारों की निम्न विशिष्ट विशेषताएं हैं:

1. **दोहरी सरकार** (अर्थात राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार)
2. लिखित संविधान
3. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के बीच शक्तियों का पृथक्करण
4. **संविधान की सर्वोच्चता**
5. कठोर संविधान
6. न्यायपालिका की स्वतंत्रता
7. द्विसदनीय विधायिका

Q.2) निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की संसदीय विधायी शक्ति के लिए प्रतिबंध / अपवाद के रूप में कार्य करता है?

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का केंद्र शासित प्रदेश
2. त्रिपुरा में स्वायत्त जिले
3. असम में जनजातीय क्षेत्र

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.2) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य

संविधान संसद के पूर्ण क्षेत्राधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाती है। दूसरे शब्दों में, संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं:
(i) राष्ट्रपति चार केंद्र शासित प्रदेशों- **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। इस विनियमन में संसद के एक अधिनियम

के समान शक्ति और प्रभाव होता है। यह इन केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद के किसी भी कार्य को निरस्त या संशोधित भी कर सकता है।
(ii) राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का एक अधिनियम राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है।
(iii) **असम** के राज्यपाल निर्देश दे सकते हैं कि संसद का एक अधिनियम राज्य में एक आदिवासी क्षेत्र (स्वायत्त जिला) पर लागू नहीं होता है या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है। राष्ट्रपति को मेघालय, **त्रिपुरा** और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों (स्वायत्त जिलों) के संबंध में भी समान शक्ति प्राप्त है।

Q.3) भारत में अवशिष्ट शक्ति के विधान के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है।
2. अवशिष्ट शक्ति के विधान में अवशिष्ट कर (residuary taxes) लगाने की शक्ति शामिल है।
3. अवशिष्ट शक्तियों की वर्तमान प्रणाली, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.3) Solution (b)

कथन 1	**कथन 2**	**कथन 3**
सत्य	**सत्य**	**असत्य**
अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति (यानी, जो मामले तीन सूचियों में से किसी में भी निहित नहीं हैं) संसद में निहित है।	कानून की इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति भी शामिल है।	1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, अवशिष्ट शक्तियां न तो संघीय विधायिका को दी गईं और न ही प्रांतीय विधायिका को बल्कि भारत के गवर्नर-जनरल में निहित थीं।

Q.4) अनुच्छेद 252 के अनुसार, जब दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभाएं संसद से राज्य सूची में किसी मामले पर कानून बनाने का अनुरोध करती हैं, तो संसद उस मामले को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है।

1. इस तरह के कानून को, उन राज्यों के आलावा जिन्होंने प्रस्तावों को पारित किया था, अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा सकता है।
2. इस तरह के कानून को केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है, न कि संबंधित राज्यों की विधानसभाओं द्वारा।
3. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 उपरोक्त प्रावधान के अनुसार पारित कानूनों का एक उदाहरण है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.4) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
एक ऐसा कानून जो केवल उन राज्यों पर लागू होता है, जिन्होंने प्रस्तावों को पारित किया है। हालाँकि, कोई अन्य राज्य अपने विधायिका में इस आशय का प्रस्ताव पारित करके बाद में इसे अपना सकते हैं।	इस तरह के कानून को केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है, न कि संबंधित राज्यों की विधानसभाओं द्वारा।	उपरोक्त प्रावधान के तहत पारित कानूनों के कुछ उदाहरण पुरस्कार प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 1955; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976; और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 हैं।

Q.5) राज्य सभा में प्रस्ताव पारित करने वाली स्थिति के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि संसद को राज्य सूची में किसी मामले पर कानून बनाना चाहिए

1. इस तरह के प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत (absolute majority) का उपयोग करके पारित किया जाता है।
2. प्रस्ताव को किसी भी समय नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं।
3. यह प्रावधान एक राज्य विधायिका की शक्ति को उसी मामले पर कानून बनाने के लिए प्रतिबंधित करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 3
d) 2 और 3

Q.5) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	असत्य
इस तरह के प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, अर्थात् विशेष बहुमत होना चाहिए।	प्रस्ताव एक वर्ष तक लागू रहता है; इसे किसी भी समय नवीनीकृत किया जा सकता है लेकिन एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं हो सकता है। प्रस्ताव के समापन के छह महीने बाद समाप्त होने वाले कानूनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है।	यह प्रावधान राज्य विधायिका की शक्ति को उसी मामले पर कानून बनाने के लिए प्रतिबंधित नहीं करता है। लेकिन, एक राज्य के कानून और एक संसदीय कानून के बीच असंगति के मामले में, उत्तरार्द्ध प्रबल होता है।

Q.6) विधानों पर केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा अपने विचारार्थ आरक्षित बिलों पर पूर्ण वीटो (absolute veto) प्राप्त होता है।
2. राज्य सूची में शामिल कुछ मामलों पर विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के साथ ही राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1

b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.6) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को उनके ऊपर पूर्ण वीटो प्राप्त होता है।	राज्य सूची में शामिल कुछ मामलों पर विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ ही राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जा सकता है। (उदाहरण के लिए, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक)।

Q.7) केंद्र-राज्य संबंधों में शक्तियों के प्रत्यायोजन (delegation) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रपति केंद्र सरकार के किसी भी कार्य को राज्य सरकार को उसकी सहमति के बिना सौंप सकता है।
2. केंद्र सरकार की सहमति से किसी राज्य का राज्यपाल उस सरकार को राज्य के किसी भी कार्यकारी कार्य को सौंप सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.7) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
राष्ट्रपति, राज्य सरकार की सहमति से, उस सरकार को केंद्र के किसी भी कार्यकारी कार्य को सौंप सकता है। संविधान उस राज्य की सहमति के बिना किसी राज्य को केंद्र के कार्यकारी कार्यों को सौंपने का भी प्रावधान करता है। लेकिन, इस मामले में, प्रत्यायोजन संसद द्वारा होता है तथा राष्ट्रपति द्वारा नहीं।	किसी राज्य का राज्यपाल, केंद्र सरकार की सहमति से, उस सरकार को राज्य के किसी भी कार्यकारी कार्य को सौंप सकता है।

Q.8) संविधान ने राज्यों की कर लगाने की शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं

1. एक राज्य विधायिका को वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कर लगाने से प्रतिबंधित किया जाता है जहां आयात या निर्यात के लिए ऐसी आपूर्ति होती है।
2. एक राज्य विधायिका किसी भी पानी (any water) के संबंध में कर लगा सकती है, लेकिन ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होना चाहिए।
3. एक राज्य विधायिका रेलवे द्वारा बिजली की खपत पर कर लगा सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.8) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
एक राज्य विधायिका को निम्नलिखित दो मामलों में वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कर लगाने से प्रतिबंधित किया गया है: (a) जहां ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर होती है; और (b) जहां इस तरह की आपूर्ति आयात या निर्यात के लिए होती है। इसके अलावा, संसद को यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों को तैयार करने का अधिकार है, जब वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति राज्य के बाहर, अथवा आयात या निर्यात के दौरान होती है।	एक राज्य विधायिका किसी भी अंतर-राज्य नदी या नदी घाटी को विनियमित करने या विकसित करने के लिए संसद द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत, निर्मित, उपभोग, वितरित या बेचे गए किसी भी पानी या बिजली के संबंध में एक कर लगा सकती है। लेकिन, ऐसा कानून, प्रभावी होने के लिए, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित होना चाहिए और उसकी सहमति प्राप्त करना चाहिए।	एक राज्य विधायिका बिजली के उपभोग या बिक्री पर कर लगा सकती है। लेकिन, निम्न स्थिति में बिजली के खपत या बिक्री पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है (a) केंद्र द्वारा उपभोग या केंद्र को बेची गई; या (b) केंद्र द्वारा या संबंधित रेलवे कंपनी द्वारा किसी भी रेलवे के निर्माण, रखरखाव या संचालन में उपभोग या केंद्र या रेलवे कंपनी को उसी उद्देश्य से बेची गयी हो।

Q.9) सांविधिक अनुदानों (statutory grants) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ये संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत प्रदान किए गए हैं।
2. ये राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं।
3. ये प्रति वर्ष भारत के समेकित कोष पर भारित होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.9) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, लेकिन प्रत्येक राज्य को नहीं। साथ ही, अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग राशि तय की जा	अनुच्छेद 275 (सामान्य और विशिष्ट दोनों) के तहत सांविधिक अनुदान राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है।	ये राशि प्रत्येक वर्ष भारत के समेकित कोष पर भारित होती है।

सकती है।		

Q.10) राज्य सरकार द्वारा उधार लेने के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. केंद्र से किसी विशेष राज्य द्वारा लिए जा सकने वाले ऋण की सीमाएं संसद द्वारा तय की जाती हैं।
2. एक राज्य सीधे विदेश से उधार नहीं ले सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.10) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**असत्य**
एक राज्य सरकार, राज्य के समेकित कोष के आधार पर भारत के भीतर उधार ले सकती है या गारंटी दे सकती है, लेकिन दोनों, उस राज्य की विधायिका द्वारा तय सीमा के भीतर होना चाहिए।	2017 में, केंद्रीय कैबिनेट ने नीतिगत दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी ताकि राज्य सरकार की संस्थाओं को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए द्विपक्षीय ओडीए (आधिकारिक विकास सहायता) भागीदारों से सीधे उधार लेने की अनुमति दी जा सके। दिशा-निर्देश राज्य सरकार की संस्थाओं को बाहरी द्विपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों से सीधे उधार लेने की सुविधा प्रदान करेंगे, जो कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन होंगी तथा वित्तपोषण एजेंसियों को ऋणों और ब्याज के सभी पुनर्भुगतान सीधे संबंधित उधारकर्ता द्वारा दिए जाएंगे। संबंधित राज्य सरकार ऋण के लिए गारंटी प्रस्तुत करेगी। भारत सरकार ऋण के लिए काउंटर गारंटी प्रदान करेगी।

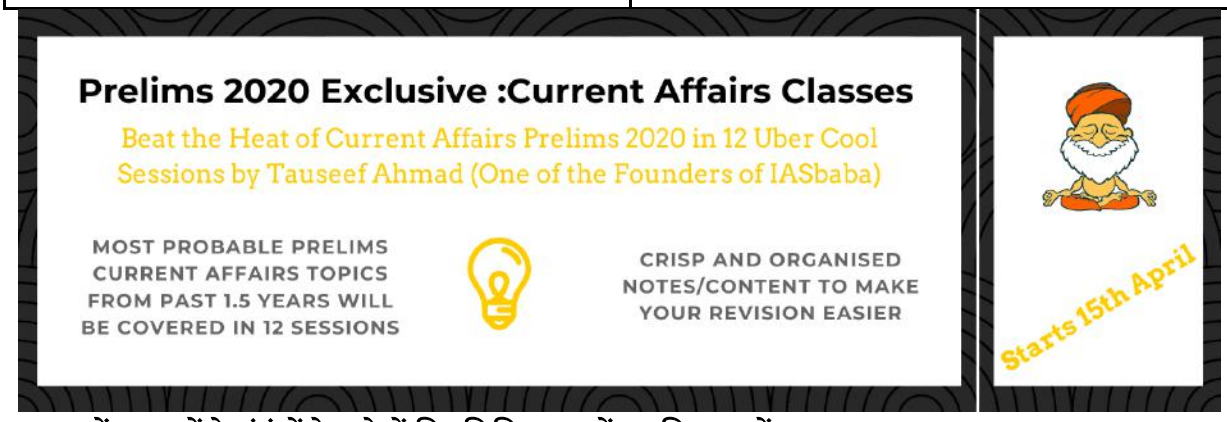

Q.11) केंद्र-राज्यों के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. केंद्र अपनी विधायी शक्तियों को राज्यों को नहीं सौंप सकता है।
2. संसद द्वारा संघ सूची के एक विषय पर बनाया गया कानून शक्तियों को प्रदान करके किसी राज्य पर शुल्कों को लागू कर सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.11) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	**सत्य**
केंद्र अपनी विधायी शक्तियों को राज्यों को नहीं सौंप सकता है तथा एक अकेला राज्य संसद से एक राज्य के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध नहीं कर सकता है।	संसद द्वारा संघ सूची के एक विषय पर बनाया गया एक कानून शक्तियों को प्रदान कर सकता है और एक राज्य पर शुल्कों को लागू कर सकता है, या एक राज्य पर केंद्र द्वारा शक्तियों के अधिरोपण और शुल्कों को लागू करने के लिए अधिकृत कर सकता है (संबंधित राज्य की सहमति के बिना भी)। विशेषकर, राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसा समान कार्य नहीं किया जा सकता है।

Q.12) वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सिफारिशों में कौन सी सिफारिशें होती हैं?

1. केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय का वितरण।
2. केंद्र द्वारा राज्यों के बीच साझा की गई कर आय का आवंटन।
3. किसी राज्य के समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.12) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	**सत्य**	**सत्य**
अनुच्छेद 280 एक वित्त आयोग को अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में प्रदान करता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें वर्ष या उससे भी पहले किया जाता है। निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति को सिफारिश करना आवश्यक है: • केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय का वितरण, तथा राज्यों के बीच आवंटन, ऐसी आय के संबंधित शेयर। • वे सिद्धांत जो केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता प्रदान करना चाहिए (अर्थात, भारत के समेकित कोष से बाहर)। • राज्य के समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों के पूरक होते हैं। • ठोस वित्त के हितों में राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी अन्य मामले को।		

Q.13) संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतरराज्यीय जल विवादों के अधिनिर्णयन का प्रावधान है। इसके तहत प्रावधान हैं

1. संसद किसी भी अंतरराज्यीय नदी के संबंध में किसी भी विवाद के अधिनिर्णयन हेतु कानून प्रदान कर सकती है।
2. राष्ट्रपति ऐसे विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.13) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों के अधिनिर्णयन का प्रावधान है। यह दो प्रावधान करता है: (i) संसद किसी भी अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत का अधिनिर्णयन करने का कानून प्रदान कर सकती है। (ii) संसद यह भी प्रदान कर सकती है कि इस तरह के किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना है।	

Q.14) अंतर-राज्य परिषद (Inter-state council) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रपति ऐसे परिषद तथा उसके संगठन और प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित कर सकते हैं।
2. यह सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।
3. प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.14) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
अनुच्छेद 263 राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए एक अंतर-राज्य परिषद की स्थापना पर विचार करता है। इस प्रकार, राष्ट्रपति इस तरह की परिषद की स्थापना कर सकते हैं यदि किसी भी समय उन्हें यह प्रतीत होता है कि इसकी स्थापना से सार्वजनिक हित में काम किया जाएगा। वह ऐसे परिषद	भारत सरकार नेअंतर-राज्य परिषद की स्थापना के लिए सरकारिया आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया तथा 1990 में अंतर-राज्य परिषद के राष्ट्रपति आदेश द्वारा स्थापना को अधिसूचित किया।	परिषद में शामिल हैं: • प्रधान मंत्री - अध्यक्ष • सभी राज्यों के मुख्यमंत्री - सदस्य • केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां विधानसभा है तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहां विधान सभा नहीं है - सदस्य

तथा उसके संगठन और प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित कर सकता है।		• केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल के छह मंत्रियों को प्रधान मंत्री द्वारा सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है

Q.15) अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह संसद को अंतर-राज्यीय नदी के संबंध में राज्यों के बीच विवाद के अधिनिर्णयन के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
2. न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवाद के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.15) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**सत्य**
अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को एक अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद के अधिनिर्णयन के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।	न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा विवाद के पक्षकारों पर बाध्य होगा। किसी भी जल विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होता है, जिसे इस अधिनियम के तहत ऐसे न्यायाधिकरण के पास भेजा जा सकता है।

Q.16) आंचलिक परिषदों (Zonal Councils) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. आंचलिक परिषदें सांविधिक निकाय हैं।
2. प्रधानमंत्री परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
3. ये सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किए गए हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.16) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	**असत्य**	**असत्य**
आंचलिक परिषद सांविधिक (और संवैधानिक नहीं) निकाय हैं। वे संसद के एक अधिनियम, अर्थात्, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए		केंद्र सरकार के गृह मंत्री पाँचों आंचलिक परिषदों के अध्यक्ष होते हैं।

हैं। इस अधिनियम ने देश को पांच क्षेत्रों (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) में विभाजित किया है तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक आंचलिक परिषद प्रदान की है।	प्रत्येक मुख्यमंत्री एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय में, रोटेशन द्वारा परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

Q.17) अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य (inter-state trade and commerce) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है।
2. किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में राज्य के साथ व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.17) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
संसद सार्वजनिक हित में व्यापार, वाणिज्य और राज्यों के बीच या राज्य के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन, संसद भारत के किसी भी हिस्से में वस्तु की कमी के मामले में एक राज्य को दूसरे राज्य पर वरीयता नहीं दे सकती है या राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है।	किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में, उस राज्य के साथ या उस राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन, इस उद्देश्य के लिए विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ ही विधायिका में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य विधायिका एक राज्य को दूसरे राज्य पर वरीयता नहीं दे सकती है या राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है।

Q.18) अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्यालय में बने रहते हैं।
2. इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा की जा सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.18) Solution (a)

कथन 1	कथन 2

सत्य	असत्य
अनुच्छेद 310 के अनुसार, रक्षा सेवाओं के सदस्य, केंद्र की नागरिक सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्र के तहत सैन्य पदों या नागरिक पदों पर रहने वाले सदस्य, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्यालय में बने रहते हैं।	अखिल भारतीय सेवाओं को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होते है, जबकि तत्काल नियंत्रण राज्य सरकारों में निहित होते है। इन अधिकारियों के खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई (दंड का प्रावधान) केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है।

Q.19) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. केंद्र की कार्यकारी शक्ति उन मामलों के संबंध में पूरे भारत में विस्तारित होती है, जिन पर संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है।
2. समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में, कार्यकारी शक्ति स्वाभाविक रूप से (by default) केंद्र के पास होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.19) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	**असत्य**
केंद्र की कार्यकारी शक्ति पूरे भारत में विस्तारित होती है: (i) उन मामलों पर, जिन पर संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है (यानी, संघ सूची में शामिल विषय); और (ii) किसी संधि या समझौते द्वारा उस पर प्रदत्त अधिकारों, अधिकरणों और प्राधिकार क्षेत्र के अभ्यास के लिए।	उन मामलों के संबंध में, जिन पर संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून की शक्ति है (अर्थात, समवर्ती सूची में शामिल विषय), कार्यकारी शक्ति राज्यों के पास होती है, सिवाय इसके कि जब कोई संवैधानिक प्रावधान या संसदीय कानून विशेष रूप से इसे केंद्र में निहित करता है ।

Q.20) केंद्र को निम्नलिखित मामलों में से अपनी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के संबंध में, राज्यों को निर्देश देने का अधिकार है

1. संचार
2. रेलवे
3. कृषि
4. भाषाई अल्पसंख्यक समूह

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1,2 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.20) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	सत्य

केंद्र को निम्नलिखित मामलों में अपनी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के संबंध में राज्यों को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है:
(i) राज्य द्वारा संचार के साधनों (राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के) का निर्माण और रखरखाव;
(ii) राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय;
(iii) राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान; तथा
(iv) राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं का निरूपण और निष्पादन।

Q.21) निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है?

1. न्यायपालिका के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति
2. व्ययों का भारत के समेकित कोष पर भारित होना
3. न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है
4. न्यायाधीशों के आचरण पर केवल संसद में चर्चा हो सकती है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 4
c) 1,2 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.21) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	असत्य
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति (जिसका अर्थ कैबिनेट की सलाह पर) द्वारा न्यायपालिका के सदस्यों (यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों) के परामर्श से किया जाता है। यह प्रावधान कार्यपालिका के पूर्ण विवेकाधिकार पर अंकुश लगाता है तथा साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक नियुक्तियां किसी भी राजनीतिक या व्यावहारिक प्रक्रियाओं पर	न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के सभी प्रशासनिक खर्चों को भारत के समेकित कोष पर भारित किया गया है। इस प्रकार, वे संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य हैं (हालांकि उन पर चर्चा की जा सकती है)।	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आवधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से केवल उस तरीके से और संविधान में वर्णित आधारों पर हटाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर नहीं रहते हैं, हालांकि वे उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अब तक नहीं हटाया गया है (या महाभियोग लगाया गया है)।	संविधान संसद में या राज्य विधानमंडल में किसी भी चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में उनके कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है, सिवाय जब महाभियोग प्रस्ताव संसद में विचाराधीन हो।

आधारित नहीं हैं।			

Q.22) सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय दे सकता है या अपनी राय देने से इंकार कर सकता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाहकारी होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.22) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**सत्य**

संविधान (अनुच्छेद 143) राष्ट्रपति को मामलों की दो श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है:

a. कानून या सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ है या जो उत्पन्न होने की संभावना है।
b. किसी भी संविधान-पूर्व संधि, समझौते, वाचा, अंतःक्रिया, या अन्य समान साधनों से उत्पन्न विवाद पर।

पहले मामले में, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या राय देने से मना कर सकता है। लेकिन, दूसरे मामले में, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को 'अवश्य' अपनी राय देनी होगी। दोनों मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाहकारी होती है तथा न्यायिक घोषणा नहीं होती है।

Q.23) अभिलेख-न्यायालय (Court of Record) के रूप में, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई हैं?

1. सर्वोच्च न्यायालय के अभिलिखित किए गए निर्णयों पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है, जब किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.23) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के पास दो शक्तियाँ हैं: a. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और कार्य सदा स्मृति और साक्ष्य के लिए दर्ज किए जाते हैं। इन अभिलेखों को स्पष्ट मूल्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर पूछताछ नहीं की जा सकती है। वे कानूनी मिसाल और कानूनी संदर्भ के रूप में पहचाने जाते हैं। b. इसमें न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, यह या तो छह महीने तक के लिए साधारण कारावास या 2,000 तक जुर्माना या दोनों के साथ होती है। 1991 में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उसके पास न केवल स्वयं की बल्कि पूरे देश में उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ अदालतों और न्यायाधिकरणों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है।	

Q.24) राष्ट्रीय आपातकाल (National emergency) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. आपातकाल की घोषणा दोनों सदनों से अनुमोदन के बिना 6 महीने से अधिक बनी रह सकती है।
2. इसे संसदीय स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
3. इसे भारत में 1975 के बाद केवल एक बार घोषित किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.24) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसकी घोषणा की तारीख से एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है, जब लोकसभा भंग कर दी गई हो या लोकसभा का विघटन एक महीने की अवधि के दौरान उद्घोषणा को मंजूरी दिए बिना हो जाता है, तो उद्घोषणा, लोकसभा के पुनर्गठन के बाद, पहली बैठक से 30 दिनों तक बनी रहती है (इसमें 6 महीने लग सकते हैं), बशर्ते राज्यसभा ने इस बीच इसे मंजूरी दे दी हो।	राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय आपातकाल की घोषणा रद्द की जा सकती है। इस तरह की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।	1975 के पश्चात् कोई भी आपातकाल लागु नहीं हुआ है, कारगिल युद्ध के दौरान भी नहीं।

Q.25) राष्ट्रीय आपातकाल (National emergency) के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

1. राज्य सरकारें निलंबित हो सकती हैं, जब आपातकालीन स्थिति संचलन में हो।
2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून, आपातकाल की समाप्ति के बाद भी परिचालन में रहते हैं।
3. आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना केंद्र से राज्यों को वित्त हस्तांतरण को रद्द कर सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.25) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	**असत्य**	**असत्य**
एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को उस तरीके के बारे में निर्देश देने के लिए विस्तारित होती है, जिस तरीके से उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाना है। सामान्य समय में, केंद्र केवल कुछ निर्दिष्ट मामलों पर किसी राज्य को कार्यकारी निर्देश दे सकता है। हालाँकि, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केंद्र किसी भी 'मामले' पर किसी राज्य को कार्यकारी निर्देश देने का हकदार बन जाता है। इस प्रकार, राज्य सरकारों को केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में लाया जाता है, हालांकि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है।	राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के छह महीने बाद निष्क्रिय हो जाते हैं।	जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा चल रही हो, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को वित्त हस्तांतरण को कम कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। इस तरह का संशोधन वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी रहता है जिसमें आपातकाल संचालित होता है। साथ ही, राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए।

Q.26) मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
2. अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं।
3. आपातकाल के दौरान ली गई विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) केवल 2
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.26) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	असत्य
अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। उनके निलंबन के लिए कोई अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 के दायरे को प्रतिबंधित कर दिया। अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकार केवल तभी निलंबित किए जा सकते हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाए, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।	44 वें संशोधन अधिनियम के बाद, अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 20) तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) आपातकाल के दौरान भी लागू रहने योग्य होता है।	44 वें संशोधन के अनुसार, केवल संबंधित कानून के तहत आपातकाल के दौरान की गई कार्यकारी कार्रवाई संरक्षित है तथा विधायी कार्रवाई संरक्षित नहीं है।

Q.27) राष्ट्रपति शासन (President's rule) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जा सकता है, जब कोई राज्य केंद्र से निर्देश का पालन करने में विफल रहता है।
2. राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
3. संसद राष्ट्रपति शासन लगने के दौरान, राज्य बजट पारित करती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.27) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
अनुच्छेद 365 कहता है कि जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी भी दिशा-निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जिसमें राज्य में शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य कर सके। ।	राष्ट्रपति शासन की घोषणा या उसकी निरंतरता को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात उस सदन के उपस्थित सदस्य और मतदान करने वालों का बहुमत हो।	राष्ट्रपति या तो राज्य विधान सभा को निलंबित या भंग करता है। संसद राज्य विधायी बिल और राज्य बजट पारित करती है।

Q.28) राष्ट्रपति शासन के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान, राज्य कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित या भंग कर दी जाती है।
2. राष्ट्रपति शासन के निरसन के लिए लोकसभा को प्रस्ताव पारित करना होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.28) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
इसके संचालन के दौरान, राज्य की कार्यकारिणी बर्खास्त कर दी जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित या भंग कर दी जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का संचालन करता है और संसद राज्य के लिए कानून बनाती है।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसे राष्ट्रपति द्वारा केवल अपनी स्वयं की शक्तियों के आधार पर निरस्त किया जा सकता है।

Q.29) वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक वर्ष संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
2. इसके संचालन के दौरान, केंद्र राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.29) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है। इसका तात्पर्य दो चीजों से है: 1. इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है; तथा 2. इसके जारी रहने के लिए बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।	वित्तीय आपातकाल के संचालन के दौरान, केंद्र वित्तीय मामलों में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है।

Q.30) बोम्मई मामले (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया, जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ हैं?

1. त्रिशंकु विधानसभा (Hung assembly)
2. कुशासन (Maladministration)
3. केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों की अवहेलना
4. कठोर वित्तीय अनिवार्यता (Stringent financial exigencies)

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 3
b) 2 और 3
c) 1,3 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.30) Solution (a)

कथन 1	कथन 3	कथन 2	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	असत्य

एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रभाव निम्नलिखित स्थितियों में उचित होगा:

1. जहां विधानसभा के आम चुनावों के बाद, कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं करती है, यानी 'त्रिशंकु विधान सभा'।
2. जहाँ विधानसभा में बहुमत रखने वाली पार्टी सरकार गठन से इंकार कर देती तथा राज्यपाल को कोई गठबंधन सरकार गठन के लिए विधानसभा में बहुमत की शक्ति वाला नहीं मिल रहा है।
3. जहां एक सरकार विधानसभा में अपनी पराजय के बाद इस्तीफा दे देती है तथा कोई अन्य पार्टी विधानसभा में बहुमत रखने वाली सरकार के गठन लिए तैयार या सक्षम नहीं होती है।
4. जहां केंद्र सरकार के एक संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है।
5. आंतरिक उपद्रव जहां, उदाहरण के लिए, एक सरकार जानबूझकर संविधान और कानून के खिलाफ काम कर रही है या एक हिंसक विद्रोह कर रही है।
6. भौतिक विखंडन, जहां सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार कर राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है।

एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुचित होगा:

1. जहां एक सरकार इस्तीफा देती है या विधानसभा में बहुमत का समर्थन खोने पर बर्खास्त कर दी जाती है तथा राज्यपाल वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना देखे बिना राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है।
2. जहां राज्यपाल स्वयं विधानसभा में एक सरकार के समर्थन का अपना आकलन करता है तथा उन्हें विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने की अनुमति दिए बिना राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है।
3. जहां विधानसभा में बहुमत का समर्थन करने वाली सत्ताधारी पार्टी को 1977 और 1980 की तरह लोकसभा के आम चुनावों में भारी हार का सामना करना पड़ा हो।
4. आंतरिक गड़बड़ी आंतरिक उपद्रव या भौतिक विखंडन की सीमा तक नहीं हो।
5. राज्य में कुप्रबंधन या सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप या राज्य की कठोर वित्तीय अनिवार्यता।
6. जहां राज्य सरकार को विनाशकारी परिणाम के लिए अत्यधिक आग्रह के मामले को छोड़कर स्वयं को सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी जाती है।
7. जहां सत्ता का उपयोग सत्ता पक्ष की अंतर-पार्टी समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है, या एक उद्देश्य के लिए जो बहिष्कृत या

	अप्रासंगिक है, जिसके लिए इसे संविधान में उल्लेख किया गया है।

Q.31) सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय करने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार है।
2. संघ सूची में मामलों के संबंध में इसके अधिकार क्षेत्र और शक्तियां संसद द्वारा विस्तारित की जा सकती हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.31) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में विवादों का निर्णय करता है। इस संबंध में, इसके पास मूल, अनन्य और अंतिम प्राधिकार है।	सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और संघ सूची में मामलों के संबंध में शक्तियां संसद द्वारा विस्तारित की जा सकती हैं। इसके अलावा, इसके अधिकार क्षेत्र और अन्य मामलों के संबंध में शक्तियों को केंद्र और राज्यों के एक विशेष समझौते द्वारा विस्तारित किया जा सकता है।

Q.32) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ किसी भी मामले में अपील करने के लिए विशेष अवकाश (special leave) देने का व्यापक विवेकाधिकार है।
2. यूएसए के विपरीत, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा का दायरा अधिक व्यापक है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.32) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण (सैन्य को छोड़कर) के फैसले के खिलाफ किसी भी मामले में अपील करने के लिए विशेष अवकाश (special leave) प्रदान करने का एक बहुत विस्तृत	भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा का

विवेकाधिकार है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी कोई पूर्ण शक्ति नहीं है।	दायरा बहुत विस्तृत है।

Q.33) भारतीय संविधान के अनुसार, न्यायिक समीक्षा का दायरा कहाँ तक सीमित है

1. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
2. कानून, उस प्राधिकरण की सक्षमता से बाहर है, जिसने उसे बनाया है
3. तर्कशीलता, उपयुक्तता या नीतिगत निहितार्थ का प्रश्न

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.33) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में निम्नलिखित तीन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। a. यह मौलिक अधिकारों (भाग III) का उल्लंघन करता है, b. यह उस प्राधिकरण की सक्षमता से बाहर है, जिसने इसे बनाया है, और c. यह संवैधानिक प्रावधानों के लिए प्रतिकूल है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय, किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय, केवल ठोस प्रश्न की जाँच करता है, अर्थात् कानून संबंधित प्राधिकारी की शक्तियों के भीतर है या नहीं। इसकी तर्कशीलता, उपयुक्तता या नीतिगत निहितार्थ के प्रश्न पर जाने की आशा नहीं है।		

Q.34) सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित याचिकाएं पीआईएल के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं?

1. महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध याचिकाएँ
2. पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित याचिकाएँ
3. उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए याचिकाएँ

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.34) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3

सत्य	सत्य	असत्य
1998 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल के रूप में प्राप्त पत्रों या याचिकाओं को देखने के लिए दिशानिर्देशों का एक समूह तैयार किया। इन दिशा-निर्देशों को 1993 और 2003 में संशोधित किया गया था। उनके अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले पत्रों या याचिकाओं को आमतौर पर जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाएगा: 1. बंधुआ श्रमिक मामले 2. उपेक्षित बच्चे 3. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना तथा सामयिक श्रमिकों का शोषण और श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें (व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर) 4. जेलों से याचिकाएं जैसे उत्पीड़न की शिकायत, पूर्व-परिपक्व रिहाई के लिए और जेल में 14 साल पूरे होने के बाद रिहाई की मांग, जेल में मौत, स्थानांतरण, व्यक्तिगत बांड पर रिहाई, मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई 5. मामला दर्ज करने से इंकार करने पर पुलिस के खिलाफ याचिका, पुलिस द्वारा उत्पीड़न और पुलिस हिरासत में मौत 6. महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ याचिकाएँ, विशेष रूप से दुल्हन, दुल्हन को जलाने, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि। 7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों से सह-ग्रामीणों या पुलिस द्वारा ग्रामीणों के उत्पीड़न या यातना की शिकायत करने वाली याचिकाएं 8. पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक संतुलन की गड़बड़ी, ड्रग्स, खाद्य अपमिश्रण, विरासत और संस्कृति के रखरखाव से संबंधित याचिकाएँ, प्राचीन वस्तुएँ, वन और वन्य जीवन और सार्वजनिक महत्व के अन्य मामले 9. दंगा-पीड़ितों से याचिकाएँ 10. पारिवारिक पेंशन		निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले मामलों को पीआईएल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा: 1. मकान मालिक-किरायेदार मामले 2. सेवा मामला तथा जो पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित हैं 3. (1 से 10 तक) पिछले बिंदुओं से संबंधित लोगों को छोड़कर केंद्र / राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें। 4. चिकित्सा और अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश 5. उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की जल्द सुनवाई के लिए याचिकाएँ

Q.35) भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संसद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित कर सकती है।
2. संसद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से समाप्त कर सकती है।
3. संसद समय-समय पर उच्च न्यायालय की सदस्य संख्या (strength) का निर्धारण करती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.35) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
संसद एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विस्तारित कर सकती है या किसी केंद्र प्रशासित क्षेत्र से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकती है।		संविधान एक उच्च न्यायालय के सदस्य संख्या को निर्दिष्ट नहीं करता है तथा इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ देता है। तदनुसार, राष्ट्रपति इसके कार्यभार के आधार पर समय-समय पर उच्च न्यायालय में सदस्य संख्या का निर्धारण करता है।

Q.36) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सी योग्यता संविधान में निर्धारित है?

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।
3. उसे दस वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.36) Solution (c)

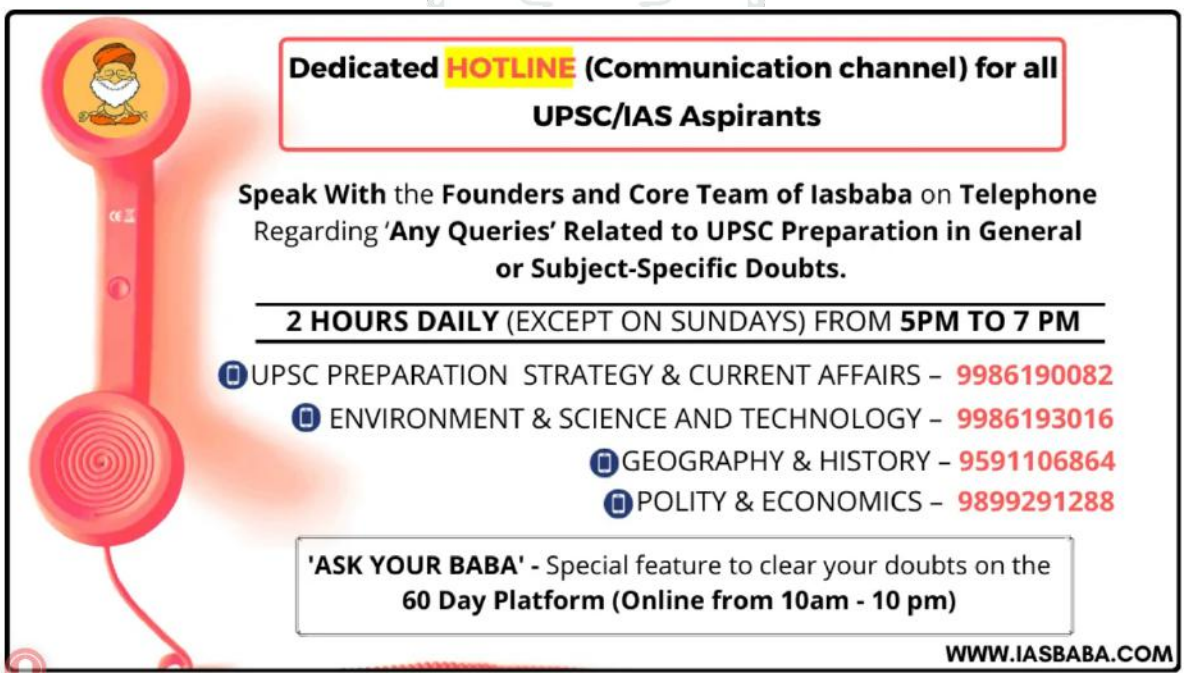

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य

एक व्यक्ति को एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए, उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. (a) उसे दस वर्षों के लिए भारत के क्षेत्र में एक न्यायिक पद रखना चाहिए; या
   (b) उन्हें दस वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए।

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के मामले के विपरीत, संविधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रतिष्ठित न्यायविद की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं करता है।

Q.37) भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. वित्तीय आपातकाल के दौरान, न्यायाधीशों के वेतन को उनकी नियुक्ति के बाद कम किया जा सकता है।
3. न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, राज्य के समेकित निधि पर भारित होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.37) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
न्यायपालिका के सदस्यों (यानी, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) के परामर्श से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति (जिसका अर्थ कैबिनेट की सलाह) द्वारा की जाती है। यह प्रावधान कार्यपालिका के पूर्ण विवेक पर अंकुश लगाता है तथा साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक नियुक्तियां किसी भी राजनीतिक या व्यावहारिक प्रक्रियाओं पर आधारित नहीं हैं।	एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन, वित्तीय आपातकाल के आलावा उनकी नियुक्ति के बाद उनके लाभ शर्तों में कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें उनके पद के कार्यकाल के दौरान समान बनी रहती हैं।	न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्चों को राज्य के समेकित निधि पर भारित किया जाता है। इस प्रकार, वे राज्य विधायिका (हालांकि इस पर चर्चा की जा सकती हैं) द्वारा गैर-मतदान योग्य होते हैं। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत के समेकित कोष पर भारित होती है, न कि राज्य पर।

Q.38) निम्नलिखित में से किस मामले में, उच्च न्यायालय भारत में मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) का आनंद लेते हैं?

1. संसद के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद
2. नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन
3. शादी और तलाक के मामले

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.38) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य

मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्च न्यायालय में प्रथम दृष्टया विवादों को सुनने की शक्ति, अपील के माध्यम से नहीं। यह निम्नलिखित तक विस्तृत है:

a. वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानूनों और अदालत की अवमानना के मामले।
b. संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद।
c. राजस्व मामले के बारे में या राजस्व संग्रह में आदेशित या किया गया अधिनियम।
d. नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन।
e. मामलों को एक अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया जिसमें संविधान की व्याख्या इसकी फाइल में शामिल थी।
f. चार उच्च न्यायालयों (यानी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों) में उच्च मूल्य के मामलों (cases of higher value) में मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र हैं।

Q.39) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तहत स्थापित कानूनी सेवा प्राधिकरणों के प्राथमिक कार्य हैं

1. पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना
2. लोक अदालतों का आयोजन करना
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.39) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तहत स्थापित कानूनी सेवा प्राधिकरण नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करते हैं:

1. पात्र व्यक्तियों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना।
2. विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करना।

Q.40) लोक अदालतों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

a) लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं।

b) लोक अदालत के पास वैसी ही शक्तियां हैं, जैसी कि एक सिविल कोर्ट में निहित होती हैं।
c) लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में निहित होती है।
d) उपरोक्त सभी सही हैं।

Q.40) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
लोक अदालत के निर्णय को दीवानी न्यायालय का आदेश या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा। लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और विवाद के सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।	लोक अदालत में उतनी ही शक्तियां हैं जितनी कि सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित हैं।	लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ कोई अपील किसी न्यायलय में नहीं होगी।

Copyright © by IASbaba

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of IASbaba.